समक्ष: रितु बहरी से पहले, न्यायमूर्ति

प्रेमवती—*अपीलकर्ता*

बनाम

हरियाणा की स्थिति और अन्य — *उत्तरदाता*

R.S.A. 2009 की संख्या 2849

13 मई 2015

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - S.10 RI.1 - पंजाब सिविल सेवा नियम,.- II, अध्याय VI, पैरा नंबर 6.17 उप नियम IV नोट 1 -मृत पति की सह-विधवा - पारिवारिक पेंशन - अपीलकर्ता ने इसके लिए **अनिवार्य निषेधाज्ञा का** मुकदमा खुद को मृतक की सह- उसने अपने पति की मृत्यु पर उसे मृतक की दूसरी विधवा के बराबर हिस्सेदारी में पेंशन लाभ देने के लिए प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 को निर्देश देने की मांग की - क्या वह विधवा है जिसकी शादी के दौरान हुई है पति की पहली पत्नी का जीवनकाल पारिवारिक पेंशन नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन का हकदार है **- अपीलकर्ता पहली पत्नी के जीवन काल के दौरान मृतक से विवाह - अपीलकर्ता का नाम मृतक की पत्नी होने के नाते नामांकित किया गया था — मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पहले मृतक की पत्नी की मृत्यु हो गई — तत्काल न्यायालय की समन्वय पीठ की जांच की गई पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 6.17 के प्रावधान, वॉल्यूम. II और आयोजित किया गया एक कर्मचारी की मृत्यु जिसकी दो पत्नियाँ थीं लेकिन पहली पत्नी पूर्व थीमृत पति, दूसरी पत्नी परिवार की पेंशन पूरी करने की हकदार है — तदनुसार, अपीलकर्ता के साथ पारिवारिक पेंशन पूरी करने का हकदार था पहली पत्नी की मृत्यु की तारीख से प्रभाव.**

ये अभिनिर्धारित किया गया है कि हाल ही में, एक मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय बेंच का *नसीब कौर वी. पंजाब राज्य और अन्य, 2014 (2) एस. सी. टी 84* जबकि पंजाब सिविल सेवाओं के नियम 6.17 के प्रावधानों की जांच करना नियम, खंड II ने ये अभिनिर्धारित किया है कि जिस कर्मचारी की दो पत्नियाँ थीं, लेकिन पहली पत्नी के पति की मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु पर दूसरी पत्नी पूरी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है। वह प्राधिकरण को एक हलफनामा प्रस्तुत करेगी कि वह एकमात्र जीवित विधवा है और कोई अन्य दावेदार नहीं है।

(पैरा 19)

***आगे,* अभिनिर्धारित किया गया, वर्तमान मामले में, मतदाता सूची की प्रति के अनुसार Ex PW4 / 1 यह दर्शाता है कि क्रम संख्या 684 पर अपीलकर्ता का नाम धरम दत्त की पत्नी के रूप में दर्ज है और दिखाया गया मकान नंबर 1999 है। अपीलकर्ता है मृतक धरम दत्त की दूसरी पत्नी थी और उसने पहली पत्नी के जीवनकाल के दौरान अपीलकर्ता से शादी की थी। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 4 अपीलकर्ता की पहली पत्नी जल्लो की मृत्यु हो गई और ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी नंबर 1 से 3 को अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश देकर अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। मुकदमा दायर करने की तारीख से मृतक धरम दत्त की सह-विधवा होने के नाते आधा हिस्सा।**

(पैरा 21)

***आगे,* अभिनिर्धारित किया गया, उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और अतिरिक्त द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 19-4-2007। जिला न्यायाधीश सोनीपत को अपास्त कर दिया गया है और विद्वान अपर द्वारा दिनांक 23.08.2006 को निर्णय और डिक्री पारित की गई है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गोहाना को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अपीलकर्ता जल्लो की मृत्यु की तारीख यानी 2.6.2005 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ पूरी पारिवारिक पेंशन का हकदार है।**

(पैरा 22)

आशीष पन्नू, एडवोकेट, *अपीलकर्ता के लिए*

सिद्धार्थ संवारिया, डीएजी, हरियाणा

निर्णय

रितु बहरी, न्यायमूर्ति :

1. वर्तमान नियमित दूसरी अपील अतिरिक्त द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 19.04.2007 के खिलाफ निर्देशित है। जिला न्यायाधीश सोनीपत द्वारा विद्वान अपर द्वारा दिनांक 23.08.2006 को निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गोहाना को अपास्त कर दिया गया।

2. वादी-अपीलकर्ता (इसके बाद 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित) ने खुद को मृतक धरम दत्त की सह-विधवा होने का दावा करते हुए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उसे पेंशन लाभ देने के लिए निर्देश देने की मांग की। अपने पति के निधन पर श्रीमती के बराबर हिस्से में जल्लो, मृतक धरम दत्त की एक और विधवा।

3. अपीलकर्ता द्वारा सामने रखा गया मामला यह है कि पति का अपीलकर्ता, धरम दत्त की दो पत्नियाँ थीं, अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 4 (मृतक के बाद से) और वह शिक्षा विभाग से सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 27.07.1991 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की, जिससे पता चलता है कि अपीलकर्ता भी उनकी पत्नी में से एक है और इस प्रकार, वह पंजाब सिविल सेवा नियम के नियम 6(17) नोट-1 और धारा 10 के अनुसार पारिवारिक पेंशन की हकदार है। , हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का नियम 1, जहां यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी चल या अचल संपत्ति उसकी दो विधवाओं को समान शेयरों में विरासत में मिलेगी, यदि वह दो विधवाओं के जीवित रहने पर मर जाता है।

4. नोटिस पर, प्रतिवादी नंबर 1 और 3 उपस्थित हुए और अपना संयुक्त लिखित बयान दाखिल किया, जिसमें उन्होंने वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए कुछ प्रारंभिक आपत्तियां लीं। योग्यता के आधार पर, यह स्वीकार किया जाता है कि धरम दत्त ने शिक्षा विभाग में सेवा की थी और उन्होंने वर्ष 1991 में सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। हालाँकि, उन्होंने कभी भी इस आशय का कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया कि उनकी दो पत्नियाँ थीं, क्योंकि पेंशन कागजात में, उन्होंने श्रीमती जल्लो, प्रतिवादी संख्या 4, उसकी एकमात्र पत्नी दिखाई थीं। उनके द्वारा प्रस्तुत परिवार के सदस्यों की सूची में अपीलकर्ता का नाम शामिल नहीं था।

5. प्रतिवादी संख्या 4 उपस्थित नहीं हुई और उस पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई लेकिन मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दिनांक 22.08.2005 के आदेश के तहत, अपीलकर्ता द्वारा अपने एलआर को रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे इस आशय की अनुमति दी गई थी कि अपीलकर्ता को आदेश 32 नियम 4 (4) सीपीसी

के तहत प्रतिवादी नंबर 4 के एलआर को पक्ष में रखने की छूट दी गई थी। इस प्रकार, एलआर को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई।

6. पक्षों की दलील से, ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए: -

"1. क्या वादी अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए डिक्री का हकदार है, जैसा कि प्रार्थना की गई है? ओपीडी
2.क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई कारण नहीं है? ओपीडी
3.क्या वादी का वाद वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नहीं है? ओपीडी
4.क्या वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने से रोका गया है? ओपीडी
5. राहत "

(7) ट्रायल कोर्ट ने पक्षों के नेतृत्व में पूरे सबूतों को देखने के बाद माना कि उत्तरदाताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि अपीलकर्ता मृतक धरम दत्त की सह-विधवा नहीं है। डी.डब्ल्यू.1 राजपाल, क्लर्क ने अपनी जिरह में अपीलकर्ता के पूरे मामले को स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने मुकदमा शुरू करने से पहले एक कानूनी नोटिस दिया था। मतदाता सूची में, अपीलकर्ता का नाम क्रम संख्या 684 पर दर्ज है और राशन कार्ड में, वह धर्म दत्त शास्त्री की पत्नी के रूप में दर्ज है। उन्होंने स्वीकार किया कि धरम दत्त ने 22.01.1991 को एक वसीयत निष्पादित की थी और उसके अनुसार अपीलकर्ता और श्रीमती जल्लो, उनकी दो विधवाएँ थीं और उपरोक्त वसीयत के आधार पर, उत्परिवर्तन संख्या 197 प्रभावी हुई थी। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि श्रीमती. जालो 02.06.2005 को समाप्त हो गया। राम पाल का जन्म मृतक धरम दत्त और अपीलकर्ता की संतान से हुआ था और उन्होंने आगे स्वीकार किया कि श्रीमती सुमन, बिमला, कलावती और सुशीला का नाम रिकॉर्ड में बेटियों के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि धर्म दत्त ने ही विभाग को गलत जानकारी दी थी, उपरोक्त स्वीकारोक्ति अपीलकर्ता द्वारा दिए गए दस्तावेजों के साथ समर्थित है, यानी मतदाता सूची Ex PW4/1 की प्रति से पता चलता है कि क्रम संख्या 684 पर अपीलकर्ता का नाम धरम दत्त की पत्नी के रूप में दर्ज है और दिखाया गया मकान नंबर 1999 है और उसी घर में प्रतिवादी संख्या 4 जल्लो को भी धरम दत्त की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। रामपाल और राकेश को मृतक धर्म दत्त के बेटों के रूप में भी दिखाया गया है। इस दस्तावेज़ को मृतक धरम दत्त की संपत्ति के उत्परिवर्तन संख्या 2174 पूर्व पीडब्लू4/1 के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। इस प्रकार अपनी वसीयत दिनांक

22.01.1991 के अनुसार, उन्होंने अपनी संपत्ति अपने दोनों बेटों रामपाल और राकेश के पक्ष में कर दी। पूर्व पीडब्लू/बी राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन की प्रति है।

(8) यह देखने के लिए कि क्या मृतक धर्म दत्त दो पत्नियाँ रखने के लिए कानून के तहत सक्षम थे, पंजाब सिविल नियमों की पारिवारिक पेंशन योजना, खंड II शीर्षक के तहत पैरा संख्या 6.17 उप नियम IV नोट 1, अध्याय VI का संदर्भ दिया गया था। उपर्युक्त नियम इस प्रकार है:-

> "जब एक सरकारी कर्मचारी एक से अधिक विधवाओं से जीवित रहता है, तो उन्हें समान हिस्से में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। किसी विधवा की मृत्यु पर, उसके हिस्से की पेंशन उसके पात्र नाबालिग बच्चे को देय हो जाएगी, यदि उसकी मृत्यु के समय, विधवा कोई पात्र नाबालिग बच्चा नहीं छोड़ती है, तो उसके हिस्से की पेंशन का भुगतान बंद हो जाएगा।"

(9) उक्त नोट को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 10 के नियम -1 के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार है: -

> "अनुसूची के वर्ग I के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का वितरण, अनुसूची के वर्ग I में वारिस, एक निर्वसीयत की संपत्ति को अनुसूची के वर्ग I के उत्तराधिकारियों के बीच निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित किया जाएगा" -
> नियम 1: निर्वसीयतकर्ता की विधवा या यदि एक से अधिक विधवाएँ हैं, तो सभी विधवाएँ एक साथ समान हिस्सा लेंगी।"

(10) उपरोक्त नियमों के अनुसार, अपीलकर्ता मृतक धरम दत्त की सह-विधवा होने के कारण श्रीमती जल्लो, प्रतिवादी संख्या 4 (मृतक) के साथ अपने मृत पति के पेंशन लाभ पाने की हकदार थी।

(11) ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अपीलकर्ता को मृतक धरम दत्त की सह-विधवा होने के नाते 1/2 हिस्से की सीमा तक पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश देकर अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। मुकदमा दायर करने की तारीख और इस तथ्य के संबंध में कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है क्योंकि धरम दत्त की मृत्यु वर्ष 1993 में हुई थी और मुकदमा वर्ष 2003 में दायर किया गया था, ट्रायल कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तक थे। अपीलकर्ता के पक्ष में ½ शेयर की सीमा तक धरम

दत्त की मासिक पेंशन जारी करने का कर्तव्य है। इस प्रकार, यह माना गया कि मुकदमा परिसीमा से बाधित नहीं है।

(12) ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, उत्तरदाताओं ने एक अपील दायर की, जिसे भी अनुमति दी गई और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए निष्कर्षों को उलट दिया गया।

(13) निचली अपीलीय अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 का उल्लेख किया है, जहां किन्हीं दो हिंदुओं के बीच विवाह संपन्न हो सकता है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात् विवाह के समय और आगे भी किसी भी पक्ष का कोई जीवनसाथी जीवित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अनुसार यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद कोई भी विवाह संपन्न होता है, तो वह शून्य और शून्य होगा और उसके किसी भी पक्ष (विवाह के खिलाफ, दूसरे पक्ष) द्वारा प्रस्तुत याचिका पर एक डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकता है। यदि यह धारा 5 के खंड I, IV और V में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो यह अशक्त हो जाएगा।

(14) उपरोक्त प्रावधानों के सह-संयुक्त पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किया गया कोई भी विवाह शून्य और अमान्य होगा। जल्लो यानी धरम दत्त की पहली पत्नी की मृत्यु वर्ष 2005 में हो गई थी, इस प्रकार, जब उसके पति ने अपीलकर्ता के साथ दूसरी शादी की थी, तब वह जीवित थी, जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अमान्य है। अपीलकर्ता को धरम दत्त की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं है और वह पारिवारिक पेंशन का दावा नहीं कर सकती। निचली अपीलीय अदालत ने मुकदमे को परिसीमा द्वारा भी वर्जित माना।

(15) कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए तैयार किए गए हैं: -

"क्या एक विधवा जिसकी शादी पहली पत्नी के जीवनकाल के दौरान हुई है, पारिवारिक पेंशन नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन की हकदार है?"

(16) इस स्तर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें **रामेश्वरी देवी बनाम बिहार राज्य** 2001(1) एस.सी.टी 1084, के मामले में नारायण लाल की दो पत्नियों को पारिवारिक पेंशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के मामले की जांच की जा रही थी।

1987 में मृत्यु हो गई, ये अभिनिर्धारित किया गया कि दूसरी पत्नी के उत्तराधिकार के अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। हालाँकि, दूसरी पत्नी के बच्चों को अपने पिता की संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने का वैध हकदार माना जाता है। दूसरी पत्नी को उस व्यक्ति की विधवा भी नहीं माना जा सकता जिसने अपनी पिछली पत्नी के जीवनकाल में उससे शादी की हो। किसी मृत कर्मचारी के सेवा लाभ उसके प्रतिवादियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को देने के उद्देश्य से, विभागीय अधिकारी स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं, भले ही पक्षों को सिविल कोर्ट से उनकी स्थिति के बारे में घोषणा न मिली हो और आनुपातिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। इसलिए। यदि उस उद्देश्य के लिए प्राधिकारी द्वारा भौतिक तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार किया गया है, तो केवल अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। पैरा 12, 13 एवं 14 में इसे निम्नानुसार अवलोकन किया गया:-

> "12. लेकिन फिर हमारे लिए इस पर विचार करना जरूरी नहीं है कि क्या नारायण लाल पर पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने पर कदाचार का आरोप लगाया जा सकता था, क्योंकि उनके जीवनकाल में उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी। वर्तमान मामले में, हम केवल इस प्रश्न से चिंतित हैं कि नारायण लाल की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का हकदार कौन है। जब किसी मृत कर्मचारी के पेंशन लाभ के लिए दो दावेदार होते हैं और जहां आवश्यक हो वहां कोई नामांकन नहीं होता है तो राज्य सरकार को सही दावेदार के बारे में जांच करनी होती है। पेंशन के वितरण के लिए तब तक इंतजार नहीं किया जा सकता जब तक कि सिविल कोर्ट पार्टियों के संबंधित अधिकारों पर फैसला नहीं सुना देता। यह निश्चित रूप से एक लंबा मामला होगा। राज्य सरकार द्वारा पेंशन लाभ का हकदार कौन है, इस पर निर्णय आने के बाद और उससे पहले भी सिविल अदालतों के दरवाजे किसी भी पक्ष के लिए हमेशा खुले रहते हैं। निःसंदेह, राज्य सरकार द्वारा की गई जांच कोई दिखावटी मामला नहीं हो सकती और यह मनमानी भी नहीं हो सकती। निर्णय प्रामाणिक और तर्कसंगत तरीके से लिया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में जांच हुई जिसे दिखावा नहीं कहा जा सकता. जांच का नतीजा यह निकला कि योगमाया देवी और नारायण लाल 1963 से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। इसलिए, एक धारणा बनती है कि नारायण लाल के साथ योगमाया देवी का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार था और एक वैध हिंदू विवाह से जुड़े सभी समारोह आयोजित किए गए थे। प्रदर्शन किया। इस अनुमान का खंडन करने में रामेश्वरी देवी असमर्थ रही हैं। फिर भी, यह योगमाया देवी और नारायण लाल के बीच विवाह को वैध नहीं बनाता है। बेशक, जब आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह का आरोप होता है, तो

अनुष्ठानों और समारोहों के उचित पालन के साथ दूसरी शादी के सख्त सबूत पर जोर दिया जाता है।

13. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि नारायण लाल और योगमाया देवी के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड (i) का उल्लंघन था और एक शून्य विवाह था। इस अधिनियम की धारा 16 के तहत, शून्य विवाह के बच्चे वैध हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत, बिना वसीयत के मरने वाले पुरुष हिंदू की संपत्ति सबसे पहले खंड (1) में उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है, जिसमें विधवा और बेटा शामिल हैं। विधवा और बेटे में से, उन सभी को शेयर मिलते हैं (धारा 8, 10 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची देखें)। योगमाया देवी को नारायण लाल की विधवा नहीं कहा जा सकता, नारायण लाल के साथ उनका विवाह शून्य है। नारायण लाल और योगमाया देवी के बीच विवाह से उत्पन्न पुत्र, नारायण लाल के वैध पुत्र होने के नाते, नारायण लाल की संपत्ति के हकदार होंगे, साथ ही वह रामेश्वरी देवी की संपत्ति के भी हकदार होंगे और रामेश्वरी देवी और नारायण लाल के विवाह से पैदा हुए पुत्र भी नारायण लाल की संपत्ति के बराबर हकदार होंगे। वह हालाँकि, यह कानूनी स्थिति है जब हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मर जाता है। यहां, हालांकि, हम पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान से चिंतित हैं जो प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि यदि उपरोक्त कानूनी स्थिति सही है, तो फैसले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं है, जिसे एलपीए में डिवीजन बेंच ने आक्षेपित फैसले द्वारा बरकरार रखा है।

14. रामेश्वरी देवी ने दो प्रमुख आपत्तियां उठाई हैं: (1) योगमाया देवी और नारायण लाल के बीच विवाह साबित नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि एक वैध हिंदू के लिए आवश्यक धार्मिक समारोहों के अनुसार विवाह के वास्तविक प्रदर्शन का कोई गवाह नहीं है। विवाह और (2) हिंदू अधिकारों के अनुसार योगमाया देवी और नारायण लाल के बीच विवाह पर सिविल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए बिना, यह नहीं माना जा सकता है कि नारायण लाल के साथ विवाह से योगमाया देवी की संतान धारा 16 के तहत वैध होगी। हिंदू विवाह अधिनियम, पहली आपत्ति पर हमने ऊपर चर्चा की है और योगमाया देवी और नारायण लाल के बीच विधिवत विवाह के पक्ष में धारणा का खंडन करने के लिए रामेश्वरी देवी द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। दूसरी आपत्ति पर, यह सही है कि योगमाया देवी और नारायण लाल के बीच हिंदू अधिकारों के अनुसार विवाह हुआ था या नहीं, इस पर किसी भी सिविल कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है।

हालाँकि, यह राज्य सरकार को ऐसे विवाह के अस्तित्व के बारे में जांच करने और योगमाया देवी के बच्चों को पेंशन और अन्य लाभ देने के लिए कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। इस पहलू पर हम पहले ही ऊपर विज्ञापित कर चुके हैं। नारायण लाल की मृत्यु के बाद राज्य सरकार द्वारा इस बात की जाँच की गई कि नारायण लाल की पत्नियों में से कौन सी उनकी कानूनी पत्नी थी। यह रामेश्वरी देवी द्वारा दायर दावों के आधार पर था। पूछताछ काफी विस्तृत थी और वास्तव में पूछताछ के दौरान दो गवाहों से पूछताछ की गई - (1) संत प्रसाद शर्मा, शिक्षक, डीएवी हाई स्कूल, दानापुर और (2) श्री बासुकीनाथ शर्मा, शाहपुर मनेर जिन्होंने योगमाया के बीच विवाह की गवाही दी। देवी और नारायण लाल ने भी यही देखा। नारायण लाल और योगमाया देवी दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे और इस विवाह से योगमाया देवी के चार बेटे पैदा हुए थे, यह भी सेवानिवृत्त चंद्र शेखर सिंह द्वारा पूछताछ के दौरान प्रमाणित किया गया है। जिला न्यायाधीश,भागलपुर,श्रीमती. (डॉ.) अरुण प्रसाद, शिवहर, श्रीमती। एस.एन. सिन्हा, पत्नी श्री एस.एन. सिन्हा, एडीएम व अन्य। अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए गए जिससे पता चला कि योगमाया देवी और नारायण लाल पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे। इसके अलावा, योगमाया देवी और नारायण लाल के बीच विवाह के बेटों को रिकॉर्ड में नारायण लाल के बेटों के रूप में दिखाया गया था।"

(17) माननीय सर्वोच्च न्यायालय **विद्याधरी और अन्य बनाम सुखराना बाई और अन्य** 2008(1) आरसीआर (सिविल) 900 के एक मामले की जांच कर रहा था जिसमें कानूनी रूप से विवाहित पत्नी अलग रह रही थी। पहली शादी के जीवित रहने और बच्चे पैदा करने के दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली। दूसरा विवाह शून्य है। पति ने पेंशन, भविष्य निधि और अन्य लाभ के लिए दूसरी पत्नी को नामांकित कर दिया। दूसरी पत्नी, हालांकि कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने की हकदार होगी। पैरा 10 और 11 में, यह निम्नानुसार अवलोकन किया गया: -

10. हालाँकि, दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय यहीं रुक गया और इस सवाल पर विचार नहीं किया कि क्या इस तथ्यात्मक परिदृश्य के बावजूद विद्याधारी को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने लगभग यह मान लिया कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए केवल कानूनी रूप से विवाहित पत्नी ही आवेदन कर सकती है, किसी अन्य को छोड़कर। उच्च न्यायालय ने स्वीकार की गई स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि यह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र शीतलदीन के भविष्य निधि, जीवन कवर योजना, पेंशन और जीवन

बीमा की राशि और मृत्यु लाभ की प्रकृति में अन्य देय राशि एकत्र करने के उद्देश्य से था। यह बात कि विद्याधरी एक नामांकित व्यक्ति थी, इस पर किसी ने विवाद नहीं किया है और इसलिए यह सिद्ध है। विद्याधारी ने उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर दावा किया था कि उसमें चार बच्चों के नाम का उल्लेख है जिनकी शीतलदीन की वैध संतान के रूप में स्थिति पर विवाद नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय ने रामेश्वरी देवी मामले (सुप्रा) में एक कथित निर्णय में यह माना है कि भले ही एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी शादी कर ली हो, ऐसी दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे अभी भी वैध होंगे, हालांकि दूसरी शादी स्वयं नहीं शून्य होगी, इसलिए, न्यायालय ने यह माना कि ऐसे बच्चे पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन दूसरी पत्नी नहीं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक था कि क्या विद्याधारी शीतलदीन के नामांकित व्यक्ति हैं? उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए वैध रूप से आवेदन दायर कर सकता है और उसे यह प्रदान किया जा सकता है। इस मुद्दे पर कानून स्पष्ट है कि विद्याधारी जैसा नामांकित व्यक्ति जो रोजगार से उत्पन्न होने वाले मृत्यु लाभों का दावा कर रहा था, वह हमेशा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत आवेदन दायर कर सकता है क्योंकि उस धारा में ऐसे नामांकित व्यक्ति को दावा करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। नामांकन के आधार पर प्रमाण पत्र. उच्च न्यायालय को यह समझना चाहिए था कि विद्याधरी न केवल एक नामांकित व्यक्ति थी, बल्कि शीतलदीन के चार बच्चों की मां भी थी, जो शीतलदीन के कानूनी उत्तराधिकारी थे और जिनके नाम फॉर्म ए में भी पाए गए थे, जो शीतलदीन ने अपने जीवनकाल के दौरान घोषणा की थी। . अपने आवेदन में विद्याधारी ने शीतलदीन के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में चार बच्चों के नाम स्पष्ट रूप से बताए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने स्वयं कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा किया है, जिस स्थिति का वह दावा नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके अलावा उसे शीतलदीन के नामांकित व्यक्ति की स्थिति प्राप्त थी। वह लंबे समय तक शीतलदीन के साथ उसकी पत्नी के रूप में रही और शीतलदीन के लिए वह एक भरोसेमंद व्यक्ति थी, जिसने उसे अपने भविष्य निधि, जीवन कवर योजना, पेंशन और जीवन बीमा की राशि और अन्य देय राशि के लिए नामांकित किया था। ऐसी परिस्थितियों में वह हमेशा सुखराना बाई जैसी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के लिए भी बेहतर थी, जो कभी शीतलदीन के साथ पत्नी के रूप में नहीं रही थी और जो शीतलदीन के कानूनी उत्तराधिकारियों को बाहर करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का दावा करने की हद तक चली गई थी। उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने में अदालत को अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है जहां प्रतिद्वंद्वी दावे, जैसा कि इस मामले में, मृतक की संपत्तियों के उत्तराधिकार

प्रमाणपत्र के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय को इन महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए था। केवल इसलिए कि सुखराना बाई कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी, वह अपने आप में विद्याधारी की तुलना में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की हकदार नहीं थी, जो पूरे समय शीतलदीन की पत्नी के रूप में रही, उसके चार बच्चों को जन्म दिया और बच्चों की ओर से भी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का दावा किया था। . हमारी राय में, न केवल शीतलदीन के नामांकित व्यक्ति को बल्कि उसके वैध कानूनी उत्तराधिकारियों को भी बाहर कर सुखराना बाई के दावे को मंजूरी देना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

11. इसलिए, हालांकि हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि सुखराना बाई अभी भी एकमात्र वैध पत्नी थी, हम सहमत होंगे विद्याधारी के पक्ष में प्रमाणपत्र देने का फैसला किया जो उनकी नामांकित व्यक्ति थीं और उनके चार बच्चों की मां थीं। हालाँकि, हमें इक्विटी को संतुलित करना होगा क्योंकि सुखराना बाई भी कानूनी उत्तराधिकारियों में से एक हैं और चार बच्चों के अलावा शीतलदीन संपत्ति में उनका बराबर का हिस्सा होगा जो कि 1/5 होगा। इसलिए, इक्विटी को संतुलित करने के लिए हमने विद्याधरी को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र देने का फैसला किया, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह शीतलदीन संपत्तियों में सुखराना बाई के 1/5वें हिस्से की रक्षा करेगी और उसे उसे सौंप देगी। नामांकित व्यक्ति के रूप में वह सुखराना बाई का 1/5वां हिस्सा ट्रस्ट में रखेंगी और सुखराना बाई को इसका भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगी। हम निर्देश देते हैं कि इस उद्देश्य के लिए वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए ट्रायल कोर्ट में सुरक्षा प्रदान करेगी।"

(18) हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय **धन्नूलाल एवं अन्य बनाम गणेशराम एवं अन्य** 2015(2) आर.सी.आर सिविल 701 के एक मामले में उस मुद्दे की जांच कर रहा था जहां पति अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद संयुक्त परिवार में अन्य महिलाओं के साथ रहना शुरू कर देता था। उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। विवाह की वैधता और उसके बच्चे की वैधता के पक्ष में मजबूत धारणा है क्योंकि दोनों के रिश्ते को सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा मान्यता दी गई थी। पैरा 13, 14 एवं 15 में इसे निम्नानुसार अवलोकन किया गया गया:-

13. **ए. डिनोहामी बनाम डब्ल्यू.एल**. के मामले में, बालाहामी, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक पुरुष और महिला पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे, कानून यह

मानेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए, कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे, न कि किसी के साथ। उपपत्नीत्व की अवस्था. न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की-

"दोनों पक्ष बीस वर्षों तक एक ही घर में एक साथ रहे, और उनके आठ बच्चे पैदा हुए। अपने जीवन के दौरान पति, अपनी पत्नी और बच्चों को स्नेहपूर्ण प्रावधानों द्वारा पहचानते थे, जिला रजिस्ट्रार के साक्ष्य से पता चलता है कि वर्षों की लंबी अवधि के लिए पार्टियों को विवाहित नागरिकों के रूप में मान्यता दी गई थी, और यहां तक कि पारिवारिक समारोहों और समारोहों में भी, जैसे, विशेष रूप से, मेजबान और परिचारिका के रूप में डॉन एंड्रीस और बालाहामी द्वारा परिवार के घर में रिश्तेदारों और अन्य मेहमानों का स्वागत - ऐसे सभी कार्य के आधार पर ही आयोजित किए गए थे। वे पुरुष और पत्नी थे। पति या पत्नी या किसी अन्य द्वारा इस संबंध को अस्वीकार करने का कोई सबूत नहीं दिया गया है।"

14. **गोकल चंद बनाम परवीन कुमारी, एआईआर 1952 एससी 231** के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि महिला का पति और पत्नी के रूप में लगातार साथ रहना और कई वर्षों तक उनके साथ ऐसा व्यवहार विवाह की धारणा को जन्म दे सकता है, लेकिन यह धारणा जो लंबे समय तक सहवास से निकाला जा सकता है, इसका खंडन किया जा सकता है और यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जो उस धारणा को कमजोर और नष्ट कर देती हैं, तो न्यायालय उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

15. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक लगातार एक साथ रहते हैं तो कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के खिलाफ मानता है। हालाँकि, इस अनुमान का खंडन निर्विवाद सबूतों के आधार पर किया जा सकता है। उस पक्ष पर भारी बोझ पड़ता है, जो रिश्ते को कानूनी मूल से वंचित करना चाहता है। वर्तमान मामले में, वादी द्वारा निर्विवाद साक्ष्य जोड़ने के बजाय, यह दलील दी गई कि प्रतिवादी इस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है कि फूलबासा बाई छत्रपति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करके सही निष्कर्ष निकाला कि फूलबासा बाई छत्रपति की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी थी।""

(19) हाल ही में, इस न्यायालय की एक समन्वयक पीठ ने **नसीब कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य** 2014 (2) एस.सी.टी 84 के एक मामले में पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के नियम 6.17 के प्रावधानों की जांच की, ये अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे कर्मचारी की मृत्यु जिसकी दो पत्नियाँ थीं लेकिन पहली पत्नी के पति की मृत्यु हो चुकी थी, दूसरी पत्नी पूरी पारिवारिक पेंशन पाने की

हकदार है। वह प्राधिकरण को एक हलफनामा प्रस्तुत करेगी कि वह एकमात्र जीवित विधवा है और कोई अन्य दावेदार नहीं है। पैरा 6 एवं 7 में इसे निम्नानुसार देखा गया है:-

> "6. तथ्यों को समग्रता में ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि पहली पत्नी के अपने पति की मृत्यु से पहले होने के संबंध में याचिकाकर्ता के विशिष्ट कथन को स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता पूरी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी यदि वह उत्तरदाताओं को एक हलफनामा प्रस्तुत करेगी कि वह एकमात्र जीवित विधवा है और कोई अन्य दावेदार नहीं है।
>
> 7. उपरोक्त शर्तों के तहत याचिका स्वीकार की जाती है और याचिकाकर्ता को पूर्ण पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाता है, जिसका लाभ उसे यथासंभव शीघ्रता से जारी किया जाएगा, अधिमानतः आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर। चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को भेजने का निर्देश दिया जाता है। "

(20) माननीय मेघालय उच्च न्यायालय ne, श्रीमती **रेनू थापा बनाम द नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य** (2014 एलआईसी 2891) के मामले में पारिवारिक पेंशन के एक मामले की जांच कर रहे थे जहां मृतक की दो पत्नियां थीं और दोनों पेंशन की राशि तय करने के लिए सहमत थीं। कानून के तहत पेंशन के कागजात दो विधवाओं के नाम पर तैयार नहीं किए जा सकते। विभाग को मृतक की पहली पत्नी के नाम पर पेंशन पत्र तैयार करने के निर्देश जारी किए गए और पहली पत्नी को समझौता पत्र के तहत सहमति के अनुसार दूसरी पत्नी के बैंक खाते में 1500/- रुपये प्रति माह जमा करने का निर्देश दिया गया। मृतक के सेवांत लाभ की शेष राशि दोनों को 50:50 के अनुपात में भुगतान करने का आदेश दिया गया।

(21) वर्तमान मामले में, मतदाता सूची Ex PW4/1 की प्रति के अनुसार, यह दर्शाता है कि क्रम संख्या 684 पर और दिखाया गया मकान नंबर 1999, अपीलकर्ता का नाम धरम दत्त की पत्नी के रूप में दर्ज है। अपीलकर्ता है मृतक धरम दत्त की दूसरी पत्नी और उसने पहली पत्नी के जीवनकाल के दौरान अपीलकर्ता से शादी की थी। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 4 जल्लो, अपीलकर्ता की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अपीलकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने का निर्देश देते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। मुकदमा दायर करने की तारीख से मृतक धरम दत्त की सह-विधवा होने के नाते आधा हिस्सा।

(22) उपर्युक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और निर्णय और डिक्री दिनांक 19.04.2007 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सोनीपत द्वारा पारित, को अपास्त कर दिया गया है और विद्वान अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) गोहाना द्वारा दिनांक 23.08.2006 को पारित निर्णय और डिक्री को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अपीलकर्ता दिनांक 02.06.2005, यानी जल्लो की मृत्यु की तारीख से पूर्ण, पारिवारिक पेंशन 9% ब्याज के साथ, की हकदार है।

अनुलेख. बाजवा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

गुरुग्राम, हरियाणा।